राष्ट्रीय मतदाता दिवस

इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, (25 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आठवां मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2019 को देश भर में मनाया गया।
- इस महत्त्वपूर्ण दिवस का आयोजन सभी भारतवासियों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है और साथ ही यह भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना बहुत जरूरी है।
- भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इस दिन को देश के लोकतंत्र का त्योहार भी कह सकते हैं। इस दिन वोट देने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जश्न का दिन होता है।
- यह दिवस मतदाताओं में मतदान प्रक्रिया में कारगर भागीदारी के बारे में जानकारी फैलाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।

उद्देश्य और विषय

- इस दिवस का उद्देश्य देश में मतदाताओं की संख्या बढ़ाना, विशेषकर नए मतदाताओं को इससे जोड़ना है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश के वोटरों को उनके अधिकारों और लोकतंत्र के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाना है।
- इस साल ये नौवां मतदाता दिवस है। इस बार की थीम – 'कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए (No Voter to be Left Behind)' रखी गई है।

9वां मतदाता दिवस

- इस बार चुनाव आयोग 9वें मतदाता दिवस पर देश भर में छह लाख से ज्यादा जगहों पर और 10 लाख के आसपास पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता दिवस मनाएगा।
- इन कार्यक्रमों में नए मतदाताओं को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनको मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए आवेदन दिए जाएंगे।

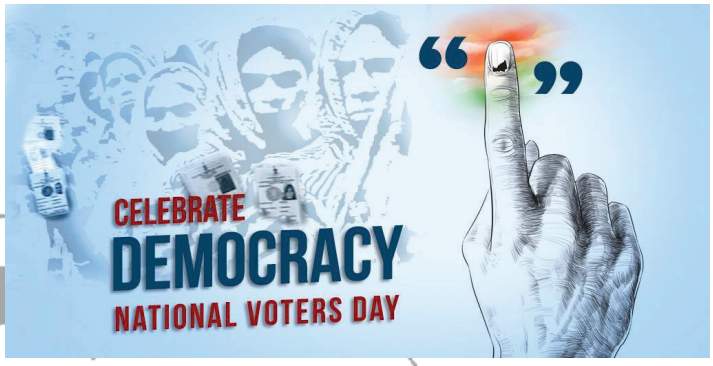

भारत निर्वाचन आयोग की शुरुआत

- भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था।
- भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही वर्ष 2011 से 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी।

भारतीय चुनाव आयोग

- भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधिक संस्थानों में जन प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था।
- आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
- संसद के दोनों सदनों-लोकसभा और राज्य सभा के लिए चुनाव बेरोक-टोक और निष्पक्ष हों, इसके लिए एक स्वतंत्र चुनाव (निर्वाचन) आयोग बनाया गया है।

यूएन की डब्ल्यूईएसपी, 2019 रिपोर्ट

इकोनामिक टाइम्स, (25 Jan.)

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2019 रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2019 और 2020 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
- रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि को मजबूत निजी उपभोग और अधिक विस्तार वाले वित्तीय रुख तथा पिछले सुधारों के लाभ से सहारा मिल रहा है।
- इसके अनुसार मध्यम अवधि की वृद्धि दर के लिए निजी निवेश में सतत सुधार महत्वपूर्ण है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर

- रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018-19 में 7.4 प्रतिशत तथा अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहेगी।
- वर्ष 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी।

निजी निवेश में सुधार

- रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यम अवधि की वृद्धि दर के लिए निजी निवेश में लगातार सुधार जरूरी है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2019 और 2020 में इसकी वृद्धि दर तीन प्रतिशत के करीब रहेगी।

चीन की रफ्तार कम होगी

- यूएन की रिपोर्ट में चीन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यहां वर्ष 2018 में विकास दर 6.6 फीसदी और वर्ष 2019 में और अधिक गिरावट के साथ 6.3 फीसदी रहने का अनुमान है।
- इसके लिए ट्रेड वॉर को भी जिम्मेदार बताया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है।
- संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई।
- वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश है, विश्व के लगभग सारे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश हैं।
- इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है।

सौर ऊर्जा और जल उपचार प्रौद्योगिकी मिशन केन्द्र

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (25 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने चेन्नई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम) में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा स्थापित तीन प्रमुख केंद्रों का शुभारंभ किया।

सौर ऊर्जा केंद्र

- इन तीनों में पहले डीएसटी- आईआईटीएम सोलर एनर्जी हारनेसिंग सेंटर की स्थापना की गई है।
- इस केंद्र में सिलिकॉन सोलर सेल जैसी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
- सिलिकॉन सोलर सेल उच्च दक्षता से युक्त हैं और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं।
- इस केंद्र में नियुक्त अनुसंधानकर्त्ताओं के नेटवर्क में आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, अन्ना विश्वविद्यालय, आईसीटी मुंबई, बीएचईएल और केजीडीएस के वैज्ञानिक शामिल हैं।

जल उपचार केंद्र

- दूसरा केंद्र डीएसटी-आईआईटीएम वॉटर-आईसी फॉर एसयूटीआरएएम ऑफ ईजी वॉटर (निपुण, सस्ते और समाधानों के लिए सतत उपचार, पुनः उपयोग और प्रबंधन के लिए डीएसटी-आईआईटीएम वॉटर इनोवेशन सेंटर) है।
- इसे अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल उपचार, सेंसर विकास, तूफान के जल के प्रबंधन, वितरण और एकत्रीकरण प्रणालियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में समावेशी अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
- यह बहुविध संस्थागत वर्चुअल केंद्र, अपशिष्ट जल उपचार, पुनःउपयोग, तूफान जल प्रबंधन के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण स्थापित करेगा।

सोलर थर्मल केंद्र

- तीसरा केंद्र 'द टेस्ट बेड ऑन सोलर थर्मल डिसेलिनेशन सोल्यूशन्स' होगा।
- इसे तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले के नारिपयूर में एक समाधान प्रदाता के रूप में आईआईटी मद्रास और इम्पीरियल केजीडीएस द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित शुष्क तटीय गांव में मौजूद जल चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी समाधान उपलब्ध कराना है।
- इसके विकास से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए तटीय क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकीय जल समाधान उपलब्ध होंगे।

आईआरईपी परियोजना

हिंदुस्तान टाइम्स, (27 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी, 2019 को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना (आईआरईपी) राष्ट्र को समर्पित किया।
- इसके साथ ही उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी।

- रिफाइनरी के उद्घाटन के अवसर पर राज्यपाल पी. सदाशिवम तथा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी उपस्थित थे।

आईआरईपी परियोजना के बारे में

- आईआरईपी की 16504 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होने वाली इस परियोजना के साथ कोच्चि रिफाइनरी प्रतिवर्ष एक करोड़ 55 लाख टन शोधन क्षमता के साथ विश्व स्तरीय रिफाइनरियों में शामिल हो जायेगी।
- यह परियोजना कोच्चि रिफाइनरी को देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी बनने में सहायक होगी।
- राज्य में 16504 करोड़ रुपये की निवेश वाली परियोजना यह एक मात्र सबसे बड़ी परियोजना है और इस परियोजना से पर्याप्त रोजगार के साथ-साथ क्षेत्र का चौतरफा आर्थिक विकास होगा।
- इस परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान 20 हजार से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए जायेंगे।
- परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद 500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

भारत में पेट्रोलियम रिफाइनरी

- कोच्चि की रिफाइनरी सहित भारत में 23 पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं।
- दिसंबर, 2017 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन सब की मिलाकर कुल क्षमता 247.6 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) है।

नीति आयोग 2.0

फाइनेंसियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, (27 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में वित्त आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष विजय केलकर ने अपने 'Towards India's New Fiscal Federalism' नामक एक आलेख में नए नीति आयोग के गठन की वकालत की है और चाहा है कि राज्यों को पूँजी एवं राजस्व अनुदान आवंटित करने का इसे उत्तरदायित्व दिया जाए।

आवश्यकता क्यों?

- योजना आयोग पहले भारत में क्षेत्रीय रूप से संतुलित वृद्धि को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन उसे हटाकर नीति आयोग नामक थिंक टैंक की स्थापना करने से सरकार की नीतियों की पहुँच पहले से घट गई है।
- इसलिए आज एक ऐसी संस्था की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए ढाँचागत सुधार लाये।

इसका कार्य क्या होगा?

- यह राज्यों को विकास के कार्यों के लिए पूँजी अथवा राजस्व अनुदान आवंटित करेगा।
- नए नीति आयोग के उपाध्यक्ष को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का एक स्थाई आमंत्रित सदस्य बनाना होगा जिससे कि यह आयोग अधिक कारगर रूप से निर्णय ले सके।
- नीति आयोग को राज्यों के वार्षिक व्यय कार्यक्रमों के अनुमोदन से दूर रखना चाहिए।
- इसकी जगह इसे एक ऐसे थिंक टैंक के रूप में काम करना चाहिए जिसके पास समुचित वित्तीय शक्ति हो और जो भारत में बदलाव लाने के लिए मध्यमकालिक एवं दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने तथा उसी हिसाब से निवेश के संसाधन जुटाने की तरफ ध्यान दे।
- नए नीति आयोग को प्रत्येक वर्ष जीडीपी के 1.5 से 2% तक की मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी जिससे कि वह विकास असंतुलन को दूर करने के लिए राज्यों को समुचित अनुदान दे सके।

इसके पक्ष में तर्क

- वर्तमान नीति आयोग हमारे अत्यंत असमान समाज को एक आधुनिक अर्थव्यस्था में रूपांतरित करने में सक्षम नहीं है।
- सार्वजनिक अथवा निजी निवेश को प्रभावित करने में नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं है।
- यह सरकार की नीति निर्माण को भी प्रभावित नहीं कर पाता जैसा कि नोटबंदी और जीएसटी के मामलों में हुआ।
- नीति आयोग को एक थिंक टैंक होना चाहिए अर्थात् उसको नए-नए विचार लाने चाहिए। परन्तु वह सरकार से एक दूरी-सी बनाए रखती है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)

इकोनॉमिक टाइम्स, (27 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में जीएसटी राजस्व में कमी देखने में आई है। इस कारण कर अधिकारियों को चिंता हो गयी है और ऐसा संभव है कि वे व्यवसाइयों द्वारा कर दायित्व को घटाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दुरुपयोग की पड़ताल करें।
- व्यवसायी इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा का दुरूपयोग कर टैक्स की चोरी कर रहे हैं, शंका व्यक्त की जा रही है।

क्या है?

- पक्के बिल से जो माल खरीदा जाता है और उसपर जो टैक्स देय होता है, उसी पर व्यवसायी को जीएसटी रिटर्न भरने से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी उत्पादनकर्ता को अपने उत्पाद को बनाने के लिए 100 रूपए का कच्चा माल खरीदना पड़ रहा है और इस पर उसे 12 फीसदी टैक्स देना पड़ता है।
- इससे अंततः उत्पादनकर्ता को कुल 112 रुपये का वहन करना पड़ता है।
- अब उत्पादनकर्ता जो सामान तैयार कर रहा है उसकी कीमत 120 रूपए हो जाती है और इस पर जीएसटी 18 फीसदी है।
- ऐसे में वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते हुए मात्र 6 फीसदी टैक्स ही चुकाएगा। इसी व्यवस्था को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं।

भूमिका

- जी. एस. टी. व्यवस्था की एक सकारात्मक विशेषता यह है कि यह कर के ऊपर कर की पूर्व की व्यवस्था से मुक्ति दिलाती है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट इसलिए लाई गई कि GST शुरू होने के पहले जो कर पर कर देना पड़ता था उस समस्या का निवारण हो सके। जीएसटी में कर पर कर नहीं लगता क्योंकि –
- अधिकांश कर मिलाकर एक कर बना दिया गया है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान कर दिया गया है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरूपयोग

- बेइमान व्यवसायी नकली बिल बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।
- देखने में आ रहा है कि किसी भी व्यवसायी को जितना जीएसटी देना है उसका 80% वह ITC से सेटल कर कर रहा है और मात्र 20% ही नकद जमा कर रहा है।
- अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस बात की जाँच हो सके ITC दावों का मिलान आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चुकाए गये कर से किया जा सके।
- इस प्रकार का मिलान ITC का दावा किये जाने के पश्चात् एक विशेष प्रणाली द्वारा किया जा रहा है जिसका नाम GSTR-2A है। मिलान हो जाने पर यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो राजस्व विभाग सम्बंधित व्यसाइयों को नोटिस भेजता है।
- वर्तमान में ITC सम्बंधित दावा प्रस्तुत होने और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चुकाए गये कर से उसका मिलान होने के बीच में समय का अंतराल होता है। इसलिए इस बात की संभावना बन जाती है कि ITC का दावा नकली इनवॉइसों के आधार पर किया जा रहा है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दसवां मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2019 को मनाया गया।
2. इसकी थीम 'कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए' रखी गयी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्था है।
2. भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट जारी की जाती है।?

(a) विश्व बैंक
(b) संयुक्त राष्ट्र
(c) वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
(d) यू.एन.डी.पी.

4. सौर ऊर्जा और जल उपचार प्रौद्योगिकी मिशन केन्द्र भारत में किस राज्य के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा स्थापित प्रमुख केन्द्रों का शुभारंभ किया गया है?

(a) तमिलनाडु (b) केरल
(c) कलकत्ता (d) उत्तर-प्रदेश

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आईआरईपी परियोजना कोच्चि रिफाइनरी को देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी बनाने में सहायक होगी।
2. भारत में कोच्चि रिफाइनरी सहित 23 पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

6. 'नीति आयोग 2.0' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. विजय केलकर ने इसके गठन की वकालत की है।
2. इस नए नीति आयोग के उपाध्यक्ष को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का एक स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाये जाने की बात की गयी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

नोट : 23-24 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(d), 3(d), 4(d), 5(a), 6(c), 7(b), 8(c) होगा।